वर्ष-10//अंक-22// जुलाई//2023

ISSN 2454–5805

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

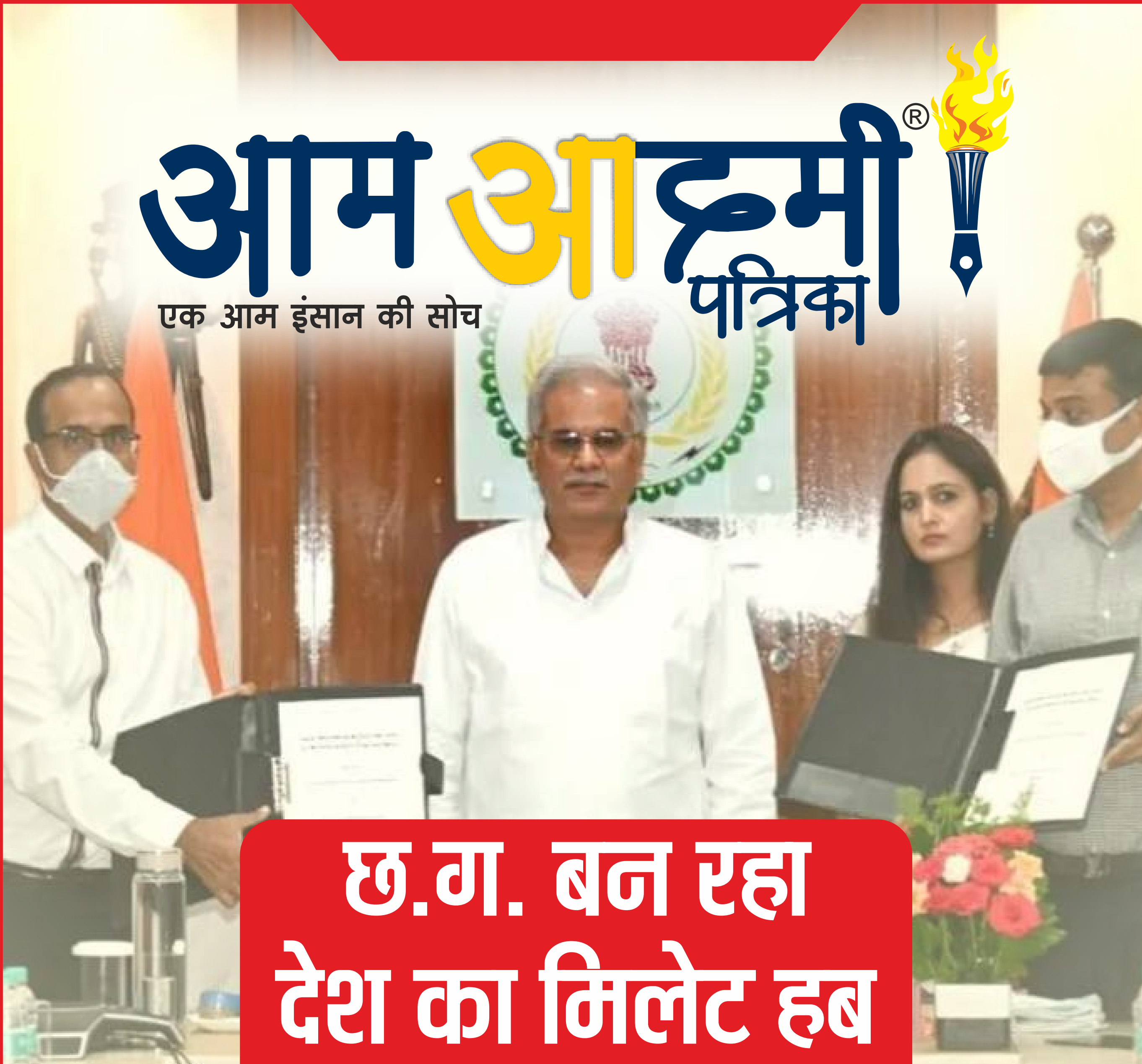

छ.ग. बन रहा देश का मिलेट हब

रीपा से ग्रामीण युवा उद्यमियों के सपनों को मिल रहा है नया आयाम

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के नये आयाम

→20

बेरोजगारी भत्ता से युवाओं को मिला संबल

→06

हाट बाजार क्लीनिक योजना बनी वरदान

→18

स्वावलंबन की दिशा में मिसाल बन रही नारी जैविक खाद से महिलाओं ने की लाखों की कमाई

MARINE DRIVE ki sham Chai Signal ke naam

अब मरीन ड्राइव Spree Walk में भी

Kulhad Ki Chai

Indian Street Snacks, Sandwiches, Maggi
Coffee, Cold Coffee

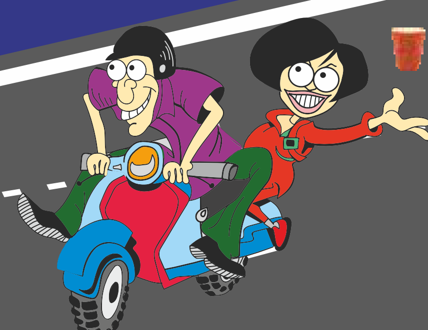

Add.: Marine Drive Spree Walk, (Beside Pizza Hut) Telibandha Talab, Raipur (C.G.)

Find us on @chaisignalcafe | www.chaisignal.com

आम आदमी पत्रिका
वर्ष-10//अंक-22// जुलाई 2023

प्रबंध संपादक	:	उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज	:	प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	:	नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	:	प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर	:	देवेन्द्र देवांगन
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर	:	आइज इवेंट्स
मार्केटिंग मैनेजर	:	किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	:	काजल सिंह
अकाउंट असिस्टेंट	:	प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	:	योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड, कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन : 0771-4044047

ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

जुलाई 2023

इस अंक में

रायपुर. छत्तीसगढ़ में सब्जी की खेती महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 38 एकड़ में फैले मल्टीएक्टिव गौठान में खुशियों की अंबार लग गई है. आलू, टमाटर, बैंगन और भिंडी की खेती से समूह की दीदियां धनवान बन रही हैं. रोजगार पाकर उनकी तकलीफें दूर हो रही हैं. समूह की दीदियां बेहतर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं. यूं कहें कि मल्टीएक्टिव गौठान सोना उगल रहा है. 38 एकड़ में फैला गौठान किसी धनकुबेर से कम नहीं है. 16

छत्तीसगढ़ के महुआ से महका परदेस 19

छत्तीसगढ़ के उत्पादों की चारो ओर चर्चा हो रही है. यहां के उत्पाद देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंच रहे हैं.

स्थानीय औषधियों पर आधारित उद्योग लाभ 33

नंदकुमार साय ने छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर.

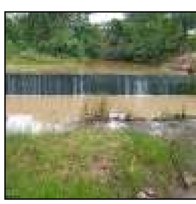

राष्ट्रीय मॉडल के रुप में उभरी नरवा योजना 35

छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा योजना अन्नदाताओं के लिए संजीवनी का काम कर रही है. अब किसानों को पानी के लिए बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है.

गुणवत्ता में श्रेष्ठ है श्री नारायणा हॉस्पिटल 12

श्री नारायणा हॉस्पिटल रायपुर में सभी के लिए एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल है.

छत्तीसगढ़ समुदाय जिनके रोम-रोम में बसते हैं राम 26

आजकल टैटू का चलन बहुत है। कोई अपने देह में प्रिय वाक्य टैटू के रूप में लगा देता है, तो कोई अपने आराध्य का टैटू लगा लेता है

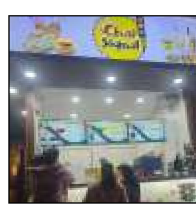

'चाय सिग्नल' अब मरीनड्राइव में भी 17

Tea Lover's के लिए चाय हर मर्ज की दवा होती है. अगर मूड खराब हो तो चाय पी लो, अगर सिर दर्द हो तो चाय

बारिश में डूबने से कैसे बचेंगे शहर

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

रिकार्डतोड़ मानसूनी बारिश ने उत्तर भारत को हलकान कर दिया है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. पहाड़ों पर तो भू-स्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, भारी बारिश की यह प्रवृत्ति अब बदलने वाली नहीं है. यह जलवायु परिवर्तन का असर है कि अब हम बार-बार मौसम की चरम अवस्था के गवाह बनने को अभिशप्त हैं. अब बारिश का पानी शहरों, विशेषकर महानगरों को ज्यादा डुबोने लगा है. इसकी वजह है. इन बड़े शहरों में जल-निकासी की व्यवस्था पंगु बना दी गई है. इससे बारिश का पानी ठहर जाता है. ऐसे में, यातायात में तो रुकावट आती ही है, बीमारियां फैलती हैं. झुग्गियों या कम आय वाले लोगों के रिहाइशी इलाके अधिक प्रभावित होते हैं और इन सबसे अधिक, लोगों की उत्पादकता घटने लगती है. ऐसा नहीं है कि छोटे शहर इन सबसे महफूज हैं. वहां भी पर्याप्त कुव्यवस्था है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों का तुलनात्मक रूप से कम होना उनके पक्ष में जाता है.

बरसात में शहरों में बाढ़ जैसे हालात बनने के पांच बड़े कारण हैं. पहला, गैर-कानूनी व बेतरतीब निर्माण-कार्य. इसमें शहरों के बाहरी हिस्सों में बनी अवैध कॉलोनियां भी शामिल हैं, जहां सड़क, नाली, सीवर आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण वहां पानी ठहर जाता है. इससे शहर के दूसरे हिस्से भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं. दूसरी वजह है, शहरी नियोजन में प्राकृतिक जल-निकासी के मार्ग की अनदेखी. बेंगलुरु इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां कभी पिनाकिनी नदी वर्षा-जल को खुद में समा लेती थी, वहां सड़कों और कॉलोनियों का जाल इस कदर फैला कि यह नदी सिमटती चली गई. नतीजतन, तकनीकी रूप से समृद्ध यह शहर अब मामूली बारिश में भी बेबस सा नजर आता है. तीसरी समस्या सीवर ओवरफ्लो की है. कई जगह सीवर व सीवेज निस्तारण वाले स्थान के स्तर में असमानता होती है. राजधानी दिल्ली में ही आईटीओ पर सीवर का गंदा पानी और वर्षा-जल मिलकर पुलिस मुख्यालय से लेकर रिंग रोड को जलमग्न कर देता है. चौथी वजह है, कूड़े का अनियोजित निस्तारण. इस समस्या के दो पहलू हैं. पहला, हमें सामान्य सूखे कचरे का उचित प्रबंधन करना होगा. इस कचरे में प्लास्टिक भी शामिल है. अब यह मान लेना हमारा भोलापन ही होगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो सकता है. चूंकि यह हमारे जीवन में रच-बस चुका है, इसलिए हमें यह व्यवस्था करनी ही होगी कि हम सूखे कचरे को अलग-अलग बांटकर उसका निस्तारण करें. इसका दूसरा पहलू मकानों का मलबा है, जिसे सीऍंडडी (कंस्ट्रक्शन ऐंड डेमोलिशन) कूड़ा कहते हैं, यानी मकानों के निर्माण-कार्य, मरम्मत, तोड़-फोड़ आदि से निकलने वाला मलबा. बड़े-बड़े शहरों में भी इसका ठीक से निस्तारण नहीं होता और नदियों या तालाबों के किनारे इसे डाल दिया जाता है. पांचवां कारण है, बरसाती पानी की नालियों, यानी 'स्टॉर्म वाटर ड्रेन' का अभाव. दिल्ली, गुरुग्राम में ही कई हिस्सों में ऐसी नालियां न होने से सड़कें जलमग्न हो जाती हैं. चूंकि अब तमाम महानगरों में जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक वर्षा होने लगी है, इसलिए हमें 'स्टॉर्म वाटर ड्रेन' की तरफ पर्याप्त ध्यान देना होगा.

देखा जाए, तो समस्या बारिश नहीं है, मुश्किलों की जड़ है, वर्षा-जल का उचित प्रबंधन न कर पाना. कई योजनाओं में इस बाबत प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हमें अब इसके लिए अलग से अभियान चलाना होगा, जिसमें सिर्फ बारिश के पानी से निपटने पर बात हो. उम्मीद है, सरकारें इस तरफ जल्द ध्यान देंगी.

बूथ चलो अभियान रायपुर पश्चिम विधानसभा में सम्पन्न हुआ मंत्री जयसिंग अग्रवाल सहित अन्य नेताओं ने संभाली बूथ की तैयारी

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा पूरे प्रदेश में जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी सहित बूथ और अनुभाग के पदाधिकारीयों की बैठक का दौर लगातार जारी है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुये कांग्रेस पार्टी ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर दी है.

छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है. बूथ चलो अभियान के तहत पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उन्हें चुनावी प्रशिक्षण दे रहे हैं. इसी कड़ी में रायपुर पश्चिम के सभी ब्लॉकों में बूथ स्तरीय बैठक आहूत की गई थी. रायपुर पश्चिम विधानसभा बूथ चलो अभियान के प्रभारी जयसिंह अग्रवाल और आर डी ए अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने जोन प्रभारियों की बैठक आज सुबह 11:00 बजे कोटा स्थित विधायक कार्यालय में ली और चुनाव की तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये. इसके पश्चात् बूथ चलो अभियान के अंतर्गत रायपुर पश्चिम विधानसभा के सरदार वल्लभभाई पटेल ब्लॉक कांग्रेस कार्यक्रम में बूथ चलो अभियान के ब्लॉक प्रभारी दुर्ग शहर के महापौर धीरज बकलीवाल ने सुबह 10:30 बजे दिशा कॉलेज के सामने साहू भवन में कार्यकर्ताओं की चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई.

इसी कड़ी में कन्हैयालाल बाजारी ब्लॉक कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के प्रभारी आरडीए अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने 11:30 बजे बूथ चलो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की चुनाव को लेकर महेश भवन गुढ़ियारी में बैठक ली और इसके उपरांत शहीद भगत सिंह ब्लॉक कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के प्रभारी बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने दोपहर 3:00 बजे मारुति लाइफ स्टाइल में बूथ चलो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली जिसमे चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई. कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बूथ चलो अभियान के दौरान मतदाता सूची का अवलोकन करते हुए जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है उनका नाम जुड़वाने और मतदाता सूची का निरीक्षण कर बूथ लेवल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर पुनरीक्षित करने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से बूथ अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं, सेक्टर व जोन प्रभारियों से आह्वान किया कि वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाएं.

हाट बाजार क्लीनिक योजना बनी वरदान
92 हजार लोगों के स्वास्थ्य की जांच और इलाज
देवदूत बनकर गांव-गांव, गली-गली जिंदगी बांट रहे डॉक्टर्स

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार की हाट बाजार क्लीनिक योजना लोगों के लिए वरदान बनकर उभरी है. ये स्कीम लोगों को नई जिंदगी परोस रही है. डॉक्टर्स गांव-गांव, गली-गली और हाट बाजारों में जाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं. ग्रामीणों में नई जान डाल रहे हैं. 11 माह में जिले में लग रही हाट-बाजारों में 92 हजार लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको दवाईयां दी गई. इस योजना ने लोगों की जिंदगी में नई उर्जा लाई है. पढ़िए बघेल सरकार की हाट बाजार क्लीनिक योजना कैसे दुर्गम पहाड़ियों में फल-फूल रही है

जांच और इलाज की सुविधा

दरअसल, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना के तहत महासमुन्द सहित विकासखण्ड बागबाहरा, बसना, सरायपाली और पिथौरा में हर हफ्तें लगने वाली हाट-बाजार में क्लिनिक स्वास्थ्य शिविर में जांच और इलाज की सुविधा मुहैया कराया जा रहा है.

स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाईयां दी गई

वहीं मरीजों को त्वरित रूप से आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है. जिले में 89 हाट बाजारों में 1822 चिकित्सक दल गए. विगत 11 माह में जिले में लग रही हाट-बाजारों में 92 हजार लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको दवाईयां दी गयी.

हाट-बाजारों में शिविर

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर होती थी, यहां प्रत्येक दिन मलेरिया से लेकर दूसरी अन्य बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है. गर्भवती महिलाओं के लिए इन इलाकों से निकलकर अस्पताल आना बेहद कठिन काम होता था. इस योजना में स्वास्थ्य अमला हाट-बाजारों में शिविर लगाकर लोगों का इलाज करने के साथ ही नि:शुल्क दवाईयां भी उपलब्ध कराते हैं. इससे ग्राम के ही नजदीक ग्रामवासी अपने स्वास्थ्य का परीक्षण और उपचार कराते हैं.

89 हाट बाजारों में क्लीनिक का संचालन

कोरोना काल के चलते पहले महासमुंद जिले के 15 हाट-बाजारों में लीनिक का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब माह अगस्त से दूरस्थ अंचलों में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों सहित 89 हाट बाजारों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजनांतर्गत स्वास्थ्य शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है.

गर्भवती महिलाओं का पंजीयन

इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, प्रसवपूर्व संपूर्ण जांच एवं पूर्ण टीकाकरण सहित बी.पी, शुगर, मलेरिया, जांच कीट के माध्यम से पैथालाजी जांच, नेत्र जांच, जागरूकता के अभाव में होने वाले अकाल मृत्यु को रोकना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, कुपोषण दर कम करना आदि है.

इन गावों में लोगों का इलाज

इस योजना से ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ हो इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर नुक्कड़ नाटकध्कलाजत्था के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में शिविर के बारे में लोगों को जानकारी देकर जन जागरूकता निर्मित की जाती है. जिले के विकासखंड बागबाहरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम चुरकी, खाट्टी, तुसदा आदि के साप्ताहिक हाट-बाजार में आये ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने बताया कि शासन की यह योजना बहुत ही फायदेमंद है.

हाट-बाजार में नियमित क्लीनिक लगने से बढ़ी भीड़

इस योजना के बारे में ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ने खुद उठा ली है. परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य जांच के लिए बाजार में लगे हाट-बाजार में भी लाते हैं. हाट-बाजार में नियमित क्लीनिक लगने से अब पहले की अपेक्षा भीड़ बढ़ी है.

क्लीनिक योजना किसी देवदूत से कम नहीं

ग्रामीण अपनी दैनिक उपयोग की सामग्री क्रय करने हेतु साप्ताहिक बाजार में आते हैं. जहां खरीदी के साथ-साथ वे अपने स्वास्थ्य की भी जांच करवा लेते हैं. दुर्गम इलाकों के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना किसी देवदूत से कम नहीं है. माह अगस्त से जिले के 89 हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जॉच कर नि:शुल्क दवाईयां मुहैया करायी जाती है.

बागबाहरा समेत इन जगहों में मिला लाभ

महासमुंद विकासखंड सहित सभी बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में लगने वाली हाट बाजारों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक शिविर का संचालन किया जा रहा है. साप्ताहिक हाट बाजारों में चिकित्सक, पैरा मेडिकल टीम के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर स्वास्थ्य उपचार किया जा रहा है.

स्वास्थ्य शिविरों में इलाज

जिले में लगाये जा रहे हाट-बाजार में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी, डायरिया, कुपोषण, एनीमिया, सिकलसेल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के साथ ही गर्भवती महिलाओं के ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन के अलावा गर्भधारण परीक्षण भी किया जा रहा है.

लाभदायक सिद्ध हो रही योजना

इसके अतिरिक्त चर्म रोग और एच.आई.वी. की भी जॉच की गई. पहले जानकारी एवं अशिक्षा के कारण अंदरूनी इलाके के ग्रामीण आसपास के बैगा-गुनिया और सिरहा से झाड़-फूक के जरिये अपना इलाज करवाते थे. सही इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु तक हो जाती थी. उन दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना अब बेहद लाभदायक सिद्ध हो रहा है.

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती शुरू हुई थी योजना

छत्तीसगढ राज्य में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जन-जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (02 अक्टूबर 2019) पर पूरे प्रदेश में यह योजना लागू की. प्रदेश के कई जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में न जाने कितने ऐसे इलाके हैं, कितने गांव हैं, जहां से निकलकर जिला मुख्यालय तक की दूरी तय कर इलाज के लिए अस्पताल आना लोगों के लिए बेहद कठिन काम होता था.

छ.ग. बन रहा देश का मिलेट हब

कोदो, कुटकी और रागी की खेती, अन्नदाताओं के खाते में बरसे 39.60 करोड़, 13 हजार टन मिलेट की खरीदी

1 लाख 60 हजार हेक्टेयर करने का लक्ष्य

रायपुर. छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार किसानों की तकदीर चमका रही है. छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बन रहा है. अन्नदाता मिलेट की खेती से बंपर मुनाफा कमा रहे हैं. खेतों में लहलहाती फसलें भूपेश सरकार की गुणगान कर रही हैं. किसानों के साथ परिवार भी खुशहाल नजर आ रहे हैं. किसानों का रूझान खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भूपेश सरकार ने किसानों की झोली में करोड़ों रुपये डाले हैं. कोदो, कुटकी और रागी की खेती करने वाले अन्नदाताओं के खाते में 39.60 करोड़ का भुगतान किया गया है. किसानों से 13 हजार टन मिलेट की खरीदी की गई है.

दरअसल, राज्य सरकार मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप किसानों का रूझान कोदो, कुटकी और रागी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है. राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी प्रारंभ किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021-22 में 16.03 करोड़ रूपए का 5 हजार 273 टन मिलेट और वर्ष 2022-23 में 39.60 करोड़ रूपए का 13 हजार 05 टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है. राज्य में खरीफ वर्ष 2023 में मिलेट्स की खेती का रकबा 96 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 01 लाख 60 हजार हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है.

मिलेट्स की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल मिलेट्स की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ-साथ इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर 03 हजार प्रति क्विंटल तथा रागी की खरीदी 3 हजार 377 रूपए प्रति क्विंटल तय की गई है. बीते सीजन में बीते सीजन में किसानों ने समर्थन मूल्य पर 34 हजार 298 क्विंटल मिलेट्स 10 करोड़ 45 लाख रूपए में बेचा था.

बल्लूराम ने रागी की खेती से कमाए 68 हजार रूपये

डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम अमलीडीह के पोषक बल्लूराम ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत धान के बदले 1 हेक्टेयर में रागी की फसल लगाई, जिसमें शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजनांतर्गत तैयार वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया तथा रागी फसल का बीज भी कृषक को नि:शुल्क प्रदाय किया गया, जिसमें फसल कटाई के बाद 12 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ. रागी को विक्रय कर उन्हें राशि 68 हजार रूपए आय प्राप्त हुई. बल्लूराम ने बताया कि लागत और मुनाफा की तुलना उसके परम्परागत धान की फसल से करने पर उनका मुनाफा लगभग डेढ़ गुना अधिक प्राप्त हुआ है. अब प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक रकबे में रागी फसल लेंगे.

पोषक तत्वों से भरपूर है मिलेट्स

देश के कई आदिवासी इलाकों में मोटे अनाज का काफी समय से प्रयोग किया जाता रहा है. यह स्वास्थ्य की पुष्टि से बहुत फायदेमंद है, इसलिए अब दूसरे इलाकों में भी इन अनाज का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. एक्सपर्ट के मुताबिक कोदो, कुटकी और रागी को प्रोटीन व विटामिन युक्त अनाज माना गया है. इसके सेवन से शुगर बीपी जैसे रोग में लाभ मिलता है. सरगुजा और बस्तर के आदिवासी संस्कृति व खानपान में कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है.

छत्तीसगढ़ को मिल चुका है राष्ट्रीय अवार्ड

गौरतलब है कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान भी मिल चुका है. राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है. मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन के लिए प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता भी दी जा रही है. मिलेट्स की खेती में कम पानी और कम खाद की जरूरत पड़ती है, जिसके फलस्वरूप इसकी खेती में लागत बेहद कम आती है और उत्पादक कृषकों को लाभ ज्यादा होता है.

14 जिलों में मिलेट की होगी हाई-टेक खेती

राज्य में मिलेट की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में मिलेट मिशन संचालित है. 14 जिलों ने आईआईएमआर हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय एमओयू भी हो चुका है. छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानि दोगुना किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है.

CM बघेल के सपने हो रहे साकार

कुपोषण की जकड़ से आजादी

रायपुर. छत्तीसगढ़ पर कुपोषण का गहरा दाग लग चुका था. सीएम भूपेश बघेल की योजनाओं ने कुपोषण पर तगड़ा प्रहार किया है. 'कुपोषण' का गहरा दाग मिट रहा है. गांव-गांव में कुपोषण पर 'सुपोषण' का प्रहार हो रहा है. बच्चों को जीवनदान देने अब जनप्रतिनिधि भी सामने आ रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं और गोद लेकर बच्चों को कुपोषण की जकड़ से आजादी दिला रहे हैं. कुपोषण की समस्या से ग्रसित जिलों में रौनक लौट रही है. बच्चे तंदुरुस्त हो रहे हैं. राज्य सरकार के सुपोषण अभियान वरदान बन रही है. ऐसी ही एक तस्वीर जशपुर में देखने को मिली, जहां सरपंच ने 20 बच्चों की जिंदगी संवार दी.

स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति का गठन

दरअसल, जिले में कुपोषण के स्तर में कमी लाने, 0-5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने, जनभागीदारी को बढ़ावा देने और एनिमिया मुक्त अभियान को सफल बनाने सुपोषण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है. कुपोषण स्तर में कमी और बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति का गठन किया गया है.

कुपोषित बच्चों के लिए बना मददगार

स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समुदाय की पहुंच, विशिष्ट स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और समुदाय आधारित योजना और निगरानी के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करने का एक मंच है, जो गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए मददगार साबित हो रहा है.

स्थानीय प्रतिनिधि अपनी सहभागिता निभा रहे

कुपोषण को दूर करने के लिए अधिकारियों द्वारा अपने चिन्हाकित गांव में जाकर सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधियों, पर्यवेक्षक, एएनएम, मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थित में सुपोषण चौपाल लगाकर बच्चों के पालकों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें सरपंच, पंच, स्थानीय प्रतिनिधि अपनी सहभागिता निभा रहे हैं.

साफ-सफाई और बच्चों के कुपोषण पर चर्चा

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के निर्देशानुसार जिले के ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वच्छता समिति का माह में एक बार बैठक आयोजित कर आंगनबाड़ी केन्द्र के मरम्मत, साफ-सफाई और बच्चों के कुपोषण पर चर्चा की जाती है.

47 बच्चों का कुपोषित श्रेणी में चिन्हांकन

इसी कड़ी में बगीचा विकासखण्ड के सेक्टर महादेवडांड के अन्तर्गत कुरोंग पंचायत में वजन त्यौहार 2022 के अनुसार कुल 47 बच्चों का कुपोषित श्रेणी में चिन्हांकन किया गया है, जिन्हें सुपोषित करने के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक आयोजित कर पोषण स्तर में सुधार हेतु सराहनीय प्रयास किया जा रहा है.

बच्चों को गोद लेकर सुपोषित कर रहे जनप्रतिनिधि

बैठक में संरपंच, उपसरपंच स्थानीय वार्ड पंच, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से शामिल होते हैं और गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लेकर सुपोषित करने का सराहनीय कार्य करते हैं.

20 बच्चों को मिली नई जिंदगी

कुरोंग पंचायत के संरपच दीपिका नागेश एवं उनके पति गोपाल नागेश ने उपसरपंच बिनोद गुप्ता के सहयोग से तीन बच्चों को एनआरसी भेजा है. इस तरह वर्तमान में कुरोंग पंचायत में कुल 27 बच्चे कुपोषित हैं. 20 बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं. जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और भी बच्चों को स्वस्थ करने की कोशिश जारी है.

गुणवत्ता में श्रेष्ठ है श्री नारायणा हॉस्पिटल

रायपुर. श्री नारायणा हॉस्पिटल (हेल्थटेक छत्तीसगढ़ प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई) रायपुर में सभी के लिए एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल है.

इसे एक विविध समाज और व्यक्ति के लिए, अपनी बीमारी की अंतिम नियति के लिए आउटलुक पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए एक विश्वसनीय हेल्थकेयर लैंडमार्क स्थापित करने के विचार के साथ बनाया गया था. यह छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित मध्य भारत के सबसे बड़े मल्टी-सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक है, जिसमें विभिन्न विशेष स्वास्थ्य संबंधी नियंत्रण सेवाएं हैं. स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना डॉ. सुनील खेमका (एमएस, एमसीएच - ऑर्थोपेडिक्स) द्वारा की गई है.

मानवता में उनके विश्वास का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञ चिकित्सा सलाहकारों और ग्राउंडेड नर्सिंग स्टाफ का उपयोग करके आधुनिक बुनियादी ढांचे के आयामों की मदद से रोगी की जरूरतों को सशक्त बनाना है. उनके प्रयासों और विश्वास से, एसएनएच रायपुर का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है.

श्री नारायणा अस्पताल का इतिहास

श्री नारायणा अस्पताल रायपुर में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है जो देवेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित है. अस्पताल की सीापना डॉ. सुनील खेमका (एम.एस., एम. सी. ऑर्थोपेडिक्स) और डॉ. मेघा खेमका द्वारा की गई है. इसने 10 जुलाई 2011 को अपना परिचालन शुरू किया. डॉ. सुनील खेमका वर्तमान में अस्पताल के प्रबंध निदेशक हैं जबकि उनकी पत्नी डॉ. मेघा खेमका अस्पताल की चिकित्सा निदेशक हैं. डॉ. सुनील खेमका ने एम.एस. पूरा किया. आर्थोपेडिक्स में पं. से. 1988 में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर जिसके बाद उन्होंने अशर्फी देवी अस्पताल, रायगढ़ में अपना व्यावसायिक करियर शुरू किया. 1990 में, डॉ. खेमका ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पर एक किराए के परिसर में अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू किया. 1993 में डॉ. खेमका ने क्लिनिक में 20 इन-पेशेंट बेड शुरू किए. 1997 में, उन्होंने रायपुर के देवेन्द्र नगर में ष्खेमका हॉस्पिटलष् नाम से 60 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम शुरू किया. 2007 में उन्होंने एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कल्पना की. 2009 में, श्री नारायण अस्पताल का निर्माण अंततः 10 जुलाई, 2011 को शुरू हुआ.

अस्पताल सराहनीय और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ है . जिसमें डॉक्टरों, सलाहकारों और कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास है. अस्पताल में सीसीयू में 250 बिस्तर और 60 क्रिटिकल केयर बिस्तर हैं, जिसमें 9 मॉड्यूलर कंप्यूटर नेविगेटेड ओटी हैं. विशेष रूप से स्थापित आइसोलेशन वार्ड, एक ब्लड बैंक, एडवांस आईवीएफ सेंटर, कैथ लैब, एमआरआई, डिजिटल सीटी स्कैन, फार्मेसी, कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया, 25 सलाहकार डॉक्टरों और 60 आवासीय डॉक्टरों के साथ, अस्पताल में चिकित्सा प्रोविडेंस के अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं. यही बात इसे रायपु में सर्वश्रेष्ठ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाती है .

ये कहानी बेमेतरा के सांकरा की है. जहां गौठान में बहनें आमदनी अर्जित कर रही हैं। पशुपालक मालामाल हो रहे हैं। वर्मी खाद बनाया जा रहा है. महिलाएं फिनाइल बना रही हैं। गौठान में चारों ओर हरियाली छाई हुई है. महिलाएं भेड़ पालन भी कर रही हैं. अलग-अलग काम से पैसे कमा रही हैं। भूपेश सरकार की योजना सुराजी गांव के तहत फेब्रिक वर्क का काम भी किया जा रहा है। बेमेतरा जिले का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श गौठानों में से एक है। जहां जिले की बहनें छोटे-छोटे व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बना रही हैं।

सुराजी गांव योजना से बही विकास की बयार

560 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन, फिनाइल निर्माण, भेंड़ पालन

पढ़िए सांकरा गौठान से बहनें कैसे बनीं आत्मनिर्भर

गोधन न्याय योजना से हो रही कमाई

सुराजी गांव योजना के अन्तर्गत नरवा गरवा घुरवा अउ बाड़ी के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिले में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहा है. ग्राम पंचायत सांकरा जनपद पंचायत बेरला से लगभग छः सात कि.मी. दूर रायपुर रोड पर स्थित है. गोधन न्याय योजना के अंतर्गत निर्मित सांकरा गौठान मुख्य मार्ग से लगा हुआ है.

गौठान में चारों ओर हरियाली

इस गौठान में एक आदर्श गौठान के लिये आवश्यक समस्त तत्व विद्यमान है। यहां के लगभग 235 पशु पालकों के 12929 पशु हैं. इस गौठान मे 44 वर्मी टांके में से 4 भरे हुये हैं. इस गौठान में लगभग 5 एकड़ रकबे में नेपियर घास लगाया गया है, जिसमें गौठान में चारों ओर हरियाली नजर आती है. इस गौठान को खूबसूरत बनाने के लिए दो एकड़ में 700 विभिन्न पौधों का रोपण किया गया है.

गौठान की हरियाली मोह लेगी मन

मुख्य मार्ग से गुजरते हुए इस गौठान की हरियाली मन को मोह लेती है. इसे एक आदर्श गौठान के रूप में विकसित किया गया है, जिसे कलेक्टर बेमेतरा ने गोद लिया है, जिससे इसके समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इसके समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है. इस कार्य योजना के पूर्ण होने के बाद यह गौठान पूरे बेमेतरा जिले का सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श गौठान सह मल्टी क्वालिटी सेंटर बनने जा रहा है.

बिहान योजना के अंतर्गत कुल बारह समूह कार्यरत

सांकरा ग्राम पंचायत में बिहान योजना के अंतर्गत कुल बारह समूह कार्यरत है. इन समूहों में से गौठान में जुड़े समूह मुख्य रूप से महिला विकास स्व-सहायता समूह संघर्ष महिला स्व-सहायता समूह, जय मां बंजारी स्व-सहायता समूह, जय मां बम्लेश्वरी स्व-सहायता समूह, और समृद्धि स्व-सहायता समूह जुड़े हैं.

स्व-सहायता समूह भेंड़ पालन का कार्य कर रहा

महिला विकास स्व सहायता समूह गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का कार्य कर रहा है. यह गौठान में ही अपना कार्य संपादित करता है. इस कार्य के अलावा यह समूह फिनाइल का भी निर्माण करता है. संघर्ष महिला स्व सहायता समूह फेब्रिक वर्क का कार्य पूरी क्षमता के साथ कर रहा है. जय मां बंजारी स्व-सहायता समूह गौठान के चारागाह में बाडी का विकास का कार्य कर रहा है. मां बमलेश्वरी स्व-सहायता समूह भेंड़ पालन का कार्य कर रहा है.

हैंडीकाफ्ट का काम कर रहा स्व सहयता समूह

गौठान से जुडा हुआ समृद्धि स्व सहयता समूह हैंडीकाफ्ट का काम कर रहा है. ये सारे समूह परोक्ष रूप से गौठान से जुडे हुए हैं और मल्टी एक्टिविटी सेन्टर के रूप में विकसित होने में अपना पूरा योगदान दे रहा है. सांकरा गौठान में 1873 क्विंटल के लगभग गोबर क्रय किया गया. इसमें 560.10 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन हुआ, जिसमें से 455.50 क्विंटल वर्मी खाद बेची गई.

मुर्गी पालन और अगरबत्ती का निर्माण

वर्तमान में 104 क्विंटल के लगभग वर्मी खाद शेष हैं. आज इस गौठान से जुड़े ये समूह अपने पैरो में खड़े होने की दिशा में आगे बढ़ रहें हैं. उनके चेहरों में सफलता की आभा देखी जा सकती है. समूह की बहनें उत्साहित होकर कहती हैं कि वे भविष्य में और भी समूहो को जोड़कर मुर्गी पालन, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादान और फल निर्माण जैसी गतिविधियों से जोडकर इस गौतान को एक अनुकारणीय आदर्श गौठान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है

मल्टीएक्टिव गौठान उगल रहा सोनारू आलू, टमाटर, बैंगन और भिंडी उगा रहीं समूह की दीदियां, 38 एकड़ में फैला है धनकुबेर गौठान

रायपुर. छत्तीसगढ़ में सब्जी की खेती महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 38 एकड़ में फैले मल्टीएक्टिव गौठान में खुशियों की अंबार लग गई है. आलू, टमाटर, बैंगन और भिंडी की खेती से समूह की दीदियां धनवान बन रही हैं. रोजगार पाकर उनकी तकलीफें दूर हो रही हैं. समूह की दीदियां बेहतर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं. यूं कहें कि मल्टीएक्टिव गौठान सोना उगल रहा है. 38 एकड़ में फैला गौठान किसी धनकुबेर से कम नहीं है.

मल्टीएक्टिविटी कार्य से मिल रही नई जिंदगी

जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम पंचायत तिलई में मल्टीएक्टिविटी का कार्य किया जा रहा है. यह मल्टीएक्टिव गौठान 38 एकड़ में फैला हुआ है. जहां स्वसहायता समूह की दीदियां सब्जियों का भरपूर उत्पादन कर रहीं है. समूह की महिलाएं कठोर परिश्रम कर अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए बेहतर स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रही हैं.

सब्जी बाड़ी का कार्य से खुशहाली के खुले द्वार

जिला प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा मल्टीएक्टिविटी कार्य अंतर्गत तिलई के गोठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रेरित करते हुए सब्जी बाड़ी का कार्य शुरू कराया गया है, जिसमें दुर्गा स्व-सहायता समूह की महिलाएं गोठान में सब्जी उत्पादन का कार्य पूरे लगन के साथ कर रहीं हैं. इस समूह की अध्यक्ष कृष्णा कौशिक और सचिव रामबाई कौशिक है.

जैविक खाद का उपयोग कर हो रही खेती

समूह की महिलाओं ने बताया कि इस सीजन में उन्होंने आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, धनिया, लगाए हैं और इसके साथ ही उनके द्वारा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए फसल उत्पादन में जैविक खाद का उपयोग भी किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वे पिछले 2 सालों से सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं और पिछले सीजन में उनके द्वारा प्याज, टमाटर, आलू, बैंगन की खेती कर 61 हजार रुपये का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं.

भिंडी, बैंगन, टमाटर और आलू की खेती

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने भिंडी, बैंगन, टमाटर और आलू की खेती की है, जिसके द्वारा अब तक टमाटर 16 क्विंटल, आलू 4 क्विंटल, बैंगन 11 क्विंटल, भिण्डी 30 किलो और फूलगोभी 25 किलो फसल लिया जा चुका है. इसके साथ ही मिर्च का उत्पादन जारी है. आगामी कुछ दिनों में प्याज का फसल भी लिया जाएगा.

हाट बाजार में भी सब्जियां बेच रहीं समूह की महिलाएं

समूह की महिलाओं की मेहनत रंग ला रही है और उनके द्वारा लगाई गई सब्जी के स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक होने के कारण आसपास के गांव के अधिकांश लोग उनसे सब्जियां खरीद रहे हैं. वहीं आसपास के हाट बाजार में भी समूह की महिलाएं सब्जियां बेच रही हैं, जिससे उन्हें बेहतर आमदनी प्राप्त हो रही है.

बैंगन के 270 पौधे रोपित किये गए

समूह द्वारा गौठान में ग्राफ्टेड बैंगन के 270 पौधे रोपित किये गए हैं, जिससे बैंगन का भरपूर उत्पादन हो रहा है. इसकी खासियत यह हैं कि इसमें विल्ट रोग नहीं लगता और इससे 45 दिनों में ही पहला फसल प्राप्त किया जा सकता है.

रायपुर में Tea Lover's के लिए एक और नया अड्डा 'चाय सिग्नल' अब मरीनड्राइव में

रायपुर. Tea Lover's के लिए चाय हर मर्ज की दवा होती है. अगर मूड खराब हो तो चाय पी लो, अगर सिर दर्द हो तो चाय या अगर मूड अच्छा हो तो भी चाय पी लो. जी हां, असली चाय लवर्स कुछ ऐसे ही होते हैं.

अब रायपुररियंस के लिए चाय की चुस्की लेने का नया अड्डा खुल गया है. ये अड्डा अब तक कटोरातालाब में ही था. लेकिन अब उनका नया अड्डा मरीन ड्राइव में भी खुल गया है. इस नए अड्डा का नाम है 'चाय सिग्नल', जहां चाय लवर्स को रूकना ही होगा.

रविवार को चाय सिग्नल का उद्घाटन हुआ, जहां बड़ी संख्या में रायपुररियंस का प्यार बारिश की हल्की बुंदों के साथ बरसा.

चाय सिग्नल में चाय के अलावा रायपुरियंस फ्राइज,सैंडविचेज, मैगी के साथ-साथ और टेस्टी फूड्स खाकर इंजॉय कर सकते है.

लवर्स के लिए चाय फीलिंग...

लवर्स के लिए चाय सिर्फ एक पीने की बात नहीं है, बल्कि ये लवर्स के लिए एक फीलिंग है. हल्के नाश्ते के साथ गर्म चाय पीना भारतीय परंपरा रही है. एक लंबे कामकाजी दिन के अंत में चाय आमतौर पर रस्क, बिस्कुट, नमकीन, समोसे और पकौड़े के साथ होती है.

स्वावलंबन की दिशा में मिसाल बन रही नारी जैविक खाद से महिलाओं ने की लाखों की कमाई

☞ पढ़िए मस्तूरी में कैसे खुले तरक्की और खुशहाली के रास्ते ☜

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तरक्की और खुशहाली के द्वार खोल रही है. जहां प्रदेश की महिलाएं खूब कमाई कर रही हैं. जैविक खाद से लाखों का मुनाफा अर्जित किया है. इसका जीता जागता उदाहरण मस्तूरी में देखने को मिला, जहां की महिलाएं स्वावलंबन की दिशा में किसी मिसाल से कम नहीं हैं. सुपर कम्पोस्ट खाद की बिक्री कर लगभग 2.50 लाख रूपये कमाए हैं. ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का कमाल है, जिसने महिलाओं को खुलहाल बना दिया.

मस्तूरी के गौठान में खुले तरक्की के द्वार

दरअसल, गोधन न्याय योजना शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई नये रास्ते खुले हैं। गौठानों में गोबर विक्रय, वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट निर्माण सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर ग्रामीण भी आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं. बड़ी संख्या में महिलाएं भी गौठानों से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं. ये महिलाएं अपने परिवार में आर्थिक भागीदारी के साथ जरूरतों को पूरा करने में भी अब अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं.

स्वावलंबन की दिशा में मिसाल बन रही नारी

बिलासपुर जिले के विकासखण्ड मस्तूरी के ग्राम पंचायत ठरकपुर में मां गायत्री स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने गौठान से जुड़कर वर्मी खाद, सुपर कम्पोस्ट, केंचुआ उत्पादन का कार्य शुरू किया है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है. ये महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही स्वावलंबन की दिशा में मिसाल बन रही हैं.

2.50 लाख रूपये का लाभ प्राप्त

समूह की अध्यक्ष विभूति कौशिक ने बताया कि वर्मी खाद जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है. अब तक उनके द्वारा 753 क्विंटल वर्मी खाद और 370 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट खाद की बिक्री की गई है, जिससे उन्हें लगभग 2.50 लाख रूपये का लाभ प्राप्त हुआ है.

मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना से खोले तरक्की के रास्ते

प्राप्त लाभ से उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई है. अन्य महिलाएं भी अपने बच्चो की शिक्षा और अन्य जरूरतें पूरे करने के लिए प्राप्त आय का उपयोग कर रही हैं. महिलाओं ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना शुरू कर गांव की तरक्की की रास्ते खोल दिए हैं.

ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली

गोधन न्याय योजना ने ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है. यहां चल रही आर्थिक गतिविधियां भी ग्रामीणों की आजीविका को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई है. पशुपालक लतेल पुरी गोस्वामी ने बताया कि उनके द्वारा 10 हजार रूपये का गोबर गौठान में बेचा गया है. ग्रामीण रामकुमार पटेल ने खुशी जाहिर कर बताया कि उन्होंने अब तक 35 हजार रूपये का गोबर बेच लिया है.

छत्तीसगढ़ के उत्पादों की चारो ओर चर्चा हो रही है. यहां के उत्पाद देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में अब यहां के महुआ की महक सात समुंदर पार पहुंच रही है. छत्तीसगढ़ में संग्रहित फूड ग्रेड महुआ फूल को राज्य लघुवनोंपज संघ द्वारा विदेश में विपणन करने की महत्वपूर्ण योजना है.

छत्तीसगढ़ के महुआ से महका परदेस

फूड ग्रेड महुआ फूल के संग्रहण से हो रहा अतिरिक्त मुनाफा

छत्तीसगढ़ में महुआ फूल की अपनी गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही नई तकनीक आदि की सुविधा से इसकी महक अब देश-विदेश तक पहुंचने लगी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में वनवासियों को लघुवनोंपजों के संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण आदि कार्यो से संग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने प्रयासरत है. इस कड़ी में फूड ग्रेड महुआ फूल का संग्रहण बहुत लाभदायी है.

503 क्विंटल से ज्यादा महुआ फूल का संग्रहण

वनमंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ से मिली जानकारी के मुताबिक जिला यूनियन मनेन्द्रगढ़ की प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति भौता, बेलबहरा, घुटरा, कछौड़, केल्हारी, बेलगांव, जुनंवा एवं माड़ीसरई के अंतर्गत फूड ग्रेड महुआ फूल (कच्चा महुआ) का नेट के माध्यम से संग्रहण कराया गया. संग्राहकों से 10.00 रु. प्रति किलोग्राम की दर से 503.65 क्विंटल कच्चा महुआ फूल संग्रहित किया गया है. संग्रहण के बाद महुआ फूल सोलर ड्रायर के माध्यम से सुखाया गया. महुआ फूल के संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों को 5 लाख 3 हजार 650 रुपये का भुगतान किया गया. सोलर ड्रायर में सुखाकर प्रसंस्करण के बाद कुल 99.60 क्विंटल (ए ग्रेड- 78.30 क्विंटल और बी ग्रेड-21.30 क्विंटल) फूड ग्रेड महुआ फूल प्राप्त हुआ. उक्त कच्चा महुआ फूल का प्रसंस्करण कार्य वन धन विकास केन्द्र जनकपुर और कठौतिया अंतर्गत स्व-सहायता समूह के 20-20 महिलाओं सदस्यों द्वारा संपन्न किया गया है. समूह की महिलाओं को माह अप्रैल से मई 2023 के मध्य 60 दिवस का रोजगार प्रदाय किया गया. महिलाओं को प्रतिदिन 200 रुपये की दर से पारिश्रमिक भुगतान किया गया है. प्रसंस्करण के बाद मिला महुआ फूल ए और बी ग्रेड का बोरा भर्ती के बाद एक्वाफुड एंड कोल्ड स्टोरेज, बिलासपुर बायपास, रिंग रोड नंबर 03 विधानसभा रोड गिरौद रायपुर में सुरक्षित भंडारण कराया गया है.

नहीं पड़ी बाजार जाने की जरुरत

फूड ग्रेड महुआ फूल को सुखाने से 5 किलोग्राम महुआ फूल से 1 किलोग्राम सूखा महुआ फूल प्राप्त होता है. इस तरह सुखा महुआ का खरीदी दर 50 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त हुआ जबकि बाजार में सूखा महुआ फूल की खरीदी दर 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम था. इस तरह फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण से हितग्राहियों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ. साथ ही महुआ पेड़ों के नीचे नेट बांधकर महुआ फूल संग्रहण करने पर तेज गर्मी के मौसम में एक-एक महुआ फूल एकत्र करने के मेहनत से संग्राहक बच गये. महुआ फूल का संग्रहण आसान हो गया. महुआ फूल को बेचने के लिए बाजार ले जाने की जरुरत नहीं पड़ी. वित्तीय वर्ष 2023-24 मे 123 महुआ हितग्राहियों के द्वारा 213 महुआ वृक्षों के नीचे नेट बांधकर फूड ग्रेड महुआ एकत्र किया गया.

स्व-सहायता समूहों को मिला अतिरिक्त रोजगार

फूड ग्रेड महुआ फूल के संग्रहण के काम को ग्रामीण बहुत पसंद कर रहे हैं. आगामी वर्षों में ज्यादा संख्या में हितग्राही नेट के माध्यम से फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण करने के लिए तैयार हुए हैं. हितग्राही इस काम के लिए काफी उत्साहित हैं. फूड ग्रेड महुआ संग्रहण के दौरान पेड़ों में नेट बांधने, संग्रहण, परिवहन, ड्रायर में सुखाने, बोरा भर्ती और जीरा निकालने के कार्य से स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ.

बेरोजगारी भत्ता से युवाओं को मिला संबल

अब पढ़ाई के आड़े नहीं आ रही घर की माली हालत

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हुई आसान

अक्सर ऐसा होता है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी रोड़ा बन जाती है. जिस वजह से वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते. लेकिन अब छत्तीसगढ़ में युवा बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं. जिसमें भूपेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना युवाओं के लिए संबल बनी.

घर के आर्थिक हालात यदि स्थिर ना हो तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च उठाना किसी भी प्रतिभागी के लिए आसान नहीं होता है. इस वजह से कई युवा घर के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ काम करने लग जाते हैं. आज के दौर में जहां नौकरियां पाने के लिए कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है. ऐसे में अपनी और घर की जरूरतों के लिए कुछ काम करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत ही कठीन हो जाता है.

अब पढ़ाई के आड़े नहीं आ रही आर्थिक स्थिति

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत चौनपुर की रहने वाली मीनू चौरसिया बताती हैं कि उनके पिता होटल व्यवसाय में काम करते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. पहले उन्हें पुस्तक, स्टेशनरी और परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक जरूरतों के लिए पैसों की बहुत दिक्कत होती थी.

मुश्किलें हुई आसान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना ने ऐसे कई युवाओं की मुश्किलों को आसान कर दिया है. इस योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपया दिया जा रहा है. बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवा अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताते हैं कि ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. उन्हें अब अपने सपनों को पूरा करने में पूरा समय मिल पाएगा.

लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिलने से उन्हें पुस्तक, कॉपी, पेन, और परीक्षा फॉर्म भरने में काफी मदद मिल रही है. उन्होंने यूटचूब में पढ़ाई करने के लिये नेट रिचार्ज भी कराया है.

मीनू चौरसिया की तरह ही अंबिकापुर में रहने वाली सुभद्रा मिंज और स्टेला लकड़ा किराए में रहकर पढ़ाई कर रही हैं. बेरोजगारी भत्ता मिलने से पुस्तक, कॉपी, पेन, प्रतियोगी पुस्तकें और परीक्षा फॉर्म भरने में काफी मदद मिल रही है. उन्होंने कहा कि हमें अब आर्थिक रूप से परिजनों पर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा. इसी तरह लखनपुर निवासी उमेश चौधरी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता का उपयोग वे अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई लिखाई की सामग्री खरीदने में कर रहे हैं जिससे उन्हें पढ़ाई में परेशानी नहीं हो रही है.

जागी उम्मीद की नई किरण

एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरी कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोरबा निवासी राजलक्ष्मी राठौर के पिता एक स्टाम्प वेंडर हैं. जिनकी आय बहुत कम है. इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. राजलक्ष्मी कहती हैं कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने से गरीब और बेरोजगार युवाओं में शासकीय नौकरी की तैयारी के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी है. इसी तरह रामपुर के रहने वाले शुभाशीष हों या छत्तीसगढ़ के दूसरे क्षेत्रों के रहने वाले गायत्री दुबे, लोकेश साहू, हीरा कुमारी महिलांग, अजय मनहर, भीषम जांगड़े, चन्द्र विजय दुबे या इनके जैसे लाखों युवा, बेरोजगारी भत्ता इनके लिए एक संबल बना है.

बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक एक लाख 5 हजार 395 युवाओं के खाते में हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है. युवा जब बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर रहे हैं, तब उन्हें प्रशिक्षण के लिए विकल्प भी दिया जा रहा है. ताकि उन्हें नौकरी या व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके. अब तक 1701 युवाओं का लाइवलीहुड कॉलेज सहित 33 संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण शुरू हो चुका है.

रीपा से ग्रामीण युवा उद्यमियों के सपनों को मिल रहा है नया आयाम

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। योजना के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड में दो गौठानों का चयन किया गया है।

ग्रामीण आजीविका पार्क में ग्रामीणों को आजीविका संवर्धन के लिए शासन की ओर से मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत संचरना जैसे आंतरिक सड़क, विद्युत, जल एवं नाली व्यवस्था, वर्कशेड, भण्डारण, प्रशिक्षण, मार्केटिंग सपोर्ट, तकनीकी मार्गदर्शन इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना में इच्छुक स्थानीय युवाओं, स्व-सहायता समूहों का चिन्हांकन कर उद्यमियों को बिजनेस प्लान के आधार पर मशीनरी तथा बैंक से ऋण, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रतानुसार अनुदान, सब्सिडी अथवा शून्य ब्याज दर पर ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे गौठानों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों में काम करने वाले ग्रामीण युवा उद्यमियों के सपनों को एक नया आयाम मिल रहा है।

ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है अतिरिक्त आय का साधन

महासमुंद जिले के बिरकोनी गौठान में महिला स्व-सहायता समूह दोना पत्तल बनाने के काम से जुड़कर आमदनी में वृद्धि कर आत्मनिर्भर बन रही है। नारी शक्ति स्व-सहायता महिला समूह में 10 महिलाएं है। पहले समूह की महिलाएं सिर्फ पैसा बचत करने तक ही सीमित थी। लेकिन हाल ही में बिरकोनी गौठान में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के अंतर्गत सीापित उद्यम महिलाओं ने दोना पत्तल बनाने का काम शुरू किया। समूह की ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (बीपीएम) सुश्री रेखा रानी नगपुरे ने बताया कि पहले यह कार्य ग्राम संगठन द्वारा किया जाता था। ग्रामीण आजीविका मिशन से मदद मिली वहीं अब रीपा के तहत स्थापित दोना पत्तल मशीन के आ जाने से काफी सहूलियत हुई है।

हाल ही में रीपा में दोना पत्तल की मशीन लगायी गयी है। प्रशासन से प्रशिक्षण के बाद काम शुरू किया गया है। अभी गांव व आसपास के क्षेत्रों में होने वाली शादी में 25 हजार से ज्यादा दोना-पत्तल बेच कर 15 हजार रूपए का मुनाफा हुआ है। समूह द्वारा तैयार किया गया दोना पत्तल की मांग आसपास के गांव तथा शहर में की जा रही है। समूह की महिलाओं ने कहा उनका दोना पत्तल का काम काफी अच्छे से चल रहा है। इससे समूह को काफी फायदा हो रहा है।

हिमाचल के बाद कर्नाटक में खुली राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पीएम मोदी की करारी हार मंत्री जगतगुरु गुरु रूद्र कुमार

रायपुर. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एकतरफा जीत हासिल की है. 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है. कांग्रेस कार्यकर्ता इस जीत का जश्न देश के सभी राज्यों में मना रहे है.

छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री जगतगुरु गुरु रूद्र कुमार ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर कहां की यह राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है. क्या शुरुआत दक्षिण के कर्नाटक से हुई है अब पूरे देश में जीत का डंका बजेगा. मंत्री जगतगुरु गुरु रूद्र कुमार ने कहा कि इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जादू नहीं चला जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रभाव का परिणाम आज देश की जनता के सामने हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के पदाधिकारियों ने कर्नाटक में जो मेहनत की उसका परिणाम है कि आज पूर्ण बहुमत से ज्यादा कांग्रेस ने जीत कर सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है.

मंत्री जगतगुरु गुरु कुमार ने कहा यह तो शुरुआत है आगे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हम पूरी इज्जत और इमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर छत्तीसगढ़ में 75 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे. छत्तीसगढ़ में पिछले साढे 4 साल में कांग्रेस ने विकास के नए-नए आयाम गढ़े हैं और इन्हीं विकास के मुद्दों के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में दूसरी बार लगातार सरकार बनाएंगे. माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमने सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य किए हैं. जिससे पिछले कई उपचुनाव, नगरी निकाय और पंचायत चुनाव में भी इसका परिणाम सफलतापूर्वक हासिल किए हैं. मैं गर्व से कहता हूं कांग्रेस पार्टी एक सच्चे और ईमानदार पार्टी है और कांग्रेस की सरकार बनने से ही जनता का कल्याण संभव है.

मंत्री जगतगुरु गुरु रूद्र कुमार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

कर्नाटक में जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है तो भाजपा में काफी निराशा दिखाई दे रही है वहीं से भाजपा की हार नहीं कांग्रेस की हार के रूप में माना जा रहे हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री जगतगुरु गुरु रूद्र कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजरंगबली पर किए गए टिप्पणी पर कहा बजरंगबली भी कांग्रेस के साथ है. इस बार भी कर्नाटक में बीजेपी ने बजरंगबली का मुद्दा उठाया था इसके जरिए भाजपा वोट बटोरने के फिराक में थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जादू ऐसा चला की पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है.

तेंदूपत्ता संग्रहण 500 करोड़ रूपए से पार संग्राहकों में बिखरी खुशियां अपार

रायपुर. छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2023 के दौरान अब तक 12 लाख 88 हजार 241 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य 16 लाख 72 हजार मानक बोरा का 77 प्रतिशत से अधिक है। इनमें तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कुल भुगतान योग्य राशि 515 करोड़ रूपए से अधिक हैं। इसका संग्रहण लगभग 11 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों द्वारा किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य सुचारू रूप से जारी है।

राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जगदलपुर वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल बीजापुर में 49 हजार 825 संग्राहकों द्वारा 32 करोड़ रूपए के 81 हजार मानक बोरा, सुकमा में 58 हजार संग्राहकों द्वारा 49 करोड़ रूपए के एक लाख 22 हजार 310 मानक बोरा, दंतेवाड़ा में 14 हजार संग्राहकों द्वारा 6 करोड़ रूपए के 15 हजार 630 मानक बोरा तथा जगदलपुर में 39 हजार संग्राहकों द्वारा 8 करोड़ 38 लाख रूपए के 20 हजार 970 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।

इसी तरह कांकेर वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल दक्षिण कोण्डागांव में 29 हजार 713 संग्राहकों द्वारा 7 करोड़ 44 लाख रूपए के 18 हजार 608 मानक बोरा, केशकाल में 33 हजार 620 संग्राहकों द्वारा 10 करोड़ रूपए के 24 हजार 963 मानक बोरा, नारायणपुर में 15 हजार 978 संग्राहकों द्वारा 7.50 करोड़ रूपए के 18 हजार 610 मानक बोरा,पूर्व भानुप्रतापपुर में 30 हजार 426 संग्राहकों द्वारा 36 करोड़ रूपए के 90 हजार 649 मानक बोरा, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 15 हजार 295 संग्राहकों द्वारा 14 करोड़ रूपए के 34 हजार 884 मानक बोरा तथा कांकेर में 31 हजार 999 संग्राकों द्वारा 13 करोड़ रूपए के 33 हजार 342 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है।

दुर्ग वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल राजनांदगांव में 44 हजार 951 संग्राहकों द्वारा 24 करोड़ रूपए के 60 हजार 588 मानक बोरा, खैरागढ़ में 22 हजार 508 संग्राहकों द्वारा 10 करोड़ रूपए के 24 हजार 516 मानक बोरा, बालोद में 20 हजार 132 संग्राहकों द्वारा 8 करोड़ रूपए के 19 हजार मानक बोरा तथा कवर्धा में 26 हजार 422 संग्राहकों द्वारा 13 करोड़ रूपए के 32 हजार 346 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। रायपुर वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल धमतरी में 25 हजार 64 संग्राहकों द्वारा 8 करोड़ रूपए के 20 हजार 584 मानक बोरा, गरियाबंद में 61 हजार 200 संग्राहकों द्वारा 31 करोड़ रूपए के 77 हजार 574 मानक बोरा, महासमुंद में 60 हजार 612 संग्राहकों द्वारा 28 करोड़ रूपए के 70 हजार 720 मानक बोरा तथा बलौदाबाजार में 18 हजार 668 संग्राहकों द्वारा 6 करोड़ रूपए के 16 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है।

बिलासपुर वनवृत्त के अंतर्गत अब तक वनमंडल बिलासपुर में 23 हजार 442 संग्राहकों द्वारा 10 करोड़ रूपए के 25 हजार 548 मानक बोरा, मरवाही में 18 हजार 78 संग्राहकों द्वारा 4 करोड़ रूपए के 10 हजार 866 मानक बोरा, जांजगीर-चांपा में 9 हजार 256 संग्राहकों द्वारा 3 करोड़ रूपए के 6 हजार 883 मानक बोरा, रायगढ़ में 43 हजार 623 संग्राहकों द्वारा 20 करोड़ रूपए के 49 हजार 184 मानक बोरा, धरमजयगढ़ में 45 हजार 204 संग्राहकों द्वारा 28 करोड़ रूपए के 70 हजार 945 मानक बोरा, कोरबा में 35 हजार 455 संग्राहकों द्वारा 18 करोड़ रूपए के 43 हजार 822 मानक बोरा तथा कटघोरा में 57 हजार 868 संग्राहकों द्वारा 24 करोड़ रूपए के 58 हजार 806 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।

इसी तरह सरगुजा वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल जशपुर में 34 हजार 262 संग्राहकों द्वारा 11 करोड़ रूपए के 27 हजार 688 मानक बोरा, मनेन्द्रगढ़ में 27 हजार 590 संग्राहकों द्वारा 12 करोड़ रूपए के 28 हजार 756 मानक बोरा, कोरिया में 28 हजार 47 संग्राहकों द्वारा 8 करोड़ रूपए के 20 हजार 958 मानक बोरा, सरगुजा में 21 हजार 983 संग्राहकों द्वारा 9 करोड़ रूपए के 22 हजार 229 मानक बोरा, बलरामपुर में 73 हजार 136 संग्राहकों द्वारा 35 करोड़ रूपए के 86 हजार 561 तथा सूरजपुर में 44 हजार 892 संग्राहकों द्वारा 21 करोड़ रूपए के 53 हजार 552 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है।

छत्तीसगढ़ में एक ऐसा समुदाय जिनके रोम-रोम में बसते हैं राम

रामनामी संप्रदाय ने पूरी तरह अपने को राम के रंग में रंग लिया है। उनका पूरा जीवन अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। उनका मानना है कि उनके भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। सच्चे भक्त की खोज भगवान को भी होती है। छत्तीसगढ़ में यह पद्य बहुत चर्चित है कि हरि का नाम तू भज ले बंदे, पाछे में पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। रामनामी संप्रदाय के हिस्से में इस पछतावे के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि उनका हर पल राम के नाम में लिप्त है। न केवल राम का नाम अपितु आचरण भी वे अपने जीवन में उतारते हैं। जिस तरह वे सुंदर मोर पंख धारण करते हैं उसी प्रकार की मन की सुंदरता भी उनके भीतर है। भगवान श्रीराम का नाम और उनका आदर्श चरित्र उनके मन को निर्मल रखता है और मयूर की तरह ही सुंदर मन के साथ वे प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं।

रायपुर, आजकल टैटू का चलन बहुत है। कोई अपने देह में प्रिय वाक्य टैटू के रूप में लगा देता है, तो कोई अपने आराध्य का टैटू लगा लेता है और कोई अन्य किसी तरह का डिजाइन बनाता है। पुराने समय में गोदना होता था और शरीर में कुछ हिस्सों में गोदना करा देते थे। भारत में गोदना हमेशा सीमित दायरे में ही रहा। पहली बार छत्तीसगढ़ में एक ऐसा संप्रदाय उभरा जिसने राम के नाम को अपने भीतर ऐसे समा लिया और राम के नाम में इतने गहराई से डूबे कि अपने सारे अंगों में राम के नाम का गोदना करा लिया। वस्त्र राम नाम से रंग लिया। भक्ति भाव की ऐसी गहन परंपरा देश में अन्यत्र दुर्लभ है।

उनका बसेरा उन्हीं क्षेत्रों में है जहां से भगवान श्रीराम के पवित्र चरण गुजरे और जिन्हें अभी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल श्रीराम वन गमन पथ के रूप में विकसित कर रहे हैं। उनका बसेरा जांजगीर चांपा, शिवरीनारायण, सारंगढ़, बिलासपुर के पूर्वी क्षेत्र में है और अधिकतर ये नदी किनारे पाए जाते हैं। भगवान श्रीराम अपने वनवास के दौरान महानदी के किनारों से गुजरे और संभवतः इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे पहले उन्होंने अपने चरित्र से प्रभावित किया होगा।

छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय के रोम-रोम में भगवान राम बसते हैं। तन से लेकर मन तक तक भगवान राम का नाम है। इस समुदाय के लिए राम सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राम भक्त लोग 'रामनामी' कहलाते हैं। राम की भक्ति भी इनके अंदर ऐसी है कि इनके पूरे शरीर पर 'राम नाम' का गोदना गुदा हुआ है। शरीर के हर हिस्से पर राम का नाम, बदन पर रामनामी चादर, सिर पर मोरपंख की पगड़ी और घुंघरू इन रामनामी लोगों की पहचान मानी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति और गुणगान ही इनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। रामनामी संप्रदाय के पांच प्रमुख प्रतीक हैं। ये हैं भजन खांब या जैतखांब, शरीर पर राम-राम का नाम गोदवाना, सफेद कपड़ा ओढ़ना, जिस पर काले रंग से राम-राम लिखा हो, घुंघरू बजाते हुए भजन करना और मोरपंखों से बना मुकट पहनना है। रामनामी समुदाय यह बताता है कि श्रीराम भक्तों की अपार श्रद्धा किसी भी सीमा से ऊपर है। प्रभु राम का विस्तार हजारों पीढ़ियों से भारतीय जनमानस में व्यापक है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी और मैदानी क्षेत्रों में सतनाम पंथ के अनुयायी सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में निवास करते है। तत्कालीन समय में जब समाज में कुरीतियां काफी व्याप्त थीं। मंदिरों में प्रवेश पर कई तरह के प्रतिबंध थे। ऐसे समय में सतनामी समाज के ही एक सदस्य वर्तमान में जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत ग्राम चारपारा निवासी श्री परशुराम ने रामनामी पंथ शुरू की थी ऐसा मानना है। यह समय सन् 1890 के आस-पास मानी जाती है।

रामनामी समाज के लोगों के अनुसार शरीर में राम-राम शब्द अंकित कराने का कारण इस शाश्वत सत्य को मानना है कि जन्म से लेकर और मृत्यु के बाद भी पूरे देह को ईश्वर को समर्पित कर देना है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य है पंक्ति के साथ अंतिम संस्कार की ओर आगे बढ़ते हैं और राम नाम सत्य के उद्घोष के साथ ही पूरा शरीर राख में परिवर्तित हो जाता है। रामनामी समाज के लोग इस हाड़-मांस रूपी देह को प्रभु श्री राम की देन मानते है। रोम-रोम में राम की उपस्थिति मानते हैं।

राम को ईष्ट देव मानकर रामनामी जीवन-मरण को जीवन के वास्तविक सार को ग्रहण करते हैं। इसी वास्तविकता को मानते हुए रामनामी समाज के लोग सम्पूर्ण शरीर में गोदना अंकित कर अपने भक्ति-भाव को राम को समर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक परंपरा है कि बड़े-छोटे, रिश्ते-नाते को सम्मान देने सुबह हो या शाम या रात्रि का समय हो राम-राम शब्द नाम का अभिवादन किया जाता है।

रामनामी अहिंसा पर विश्वास करते है। सत्य बोलते है। सात्विक भोजन करते हैं। सतनाम पंथ के लोग सतनाम की आराधना करते है, वहीं रामनामी राम की आराधना करते हैं। संतनाम पंथ के संस्थापक संत गुरू घासीदास बाबा ने कहा है कि 'अपन घट के ही देव ला मनइबो, मंदिरवा में का करे जइबों के जरिए अपने शरीर को ही मंदिर मानकर उन्हीं की पूजा आराधना व विचार को बदलने की बात कही है, वहीं रामनामी संप्रदाय के लोगों ने भी मंदिर और मूर्ति के बजाय अपने रोम-रोम में ही राम को बसा लिया और तन को मंदिर बना दिया। अब इस समाज के सभी लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। इनकी एक अलग पहचान है। पूरे बदन पर राम नाम का गुदना गुदवाते हैं। घरों की दीवारों पर राम के ही चित्र होते है। अभिवादन भी राम का नाम लेकर करते हैं।

मानव तन ईश्वर का सबसे सुंदर रूप माना जाता है। रामनामी संप्रदाय के लोगों ने इस सुंदर रूप में राम को बसाकर उसकी सुंदरता में चार चाँद लगा दिये हैं। उनकी भक्ति की श्रेष्ठ परंपरा के आगे हम सब नतमस्तक हैं.

विशेष लेख : छत्तीसगढ़ में

सबका बढ़ता मान

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई न्याय योजनाओं से समाज के शोषित वंचित और गरीब सबका न केवल मान बढ़ा है बल्कि इन योजनाओं की बयार से बड़ी राहत मिल रही हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जैसी नवाचारी पहल से लोगों को आसानी से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रहीं हैं। बेरोजगारों को प्रतिमाह भत्ता मिलना प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों की भी चिंता करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि कर उनका मान बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस पर श्रमिकों का मान बढ़ाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में इन्हें देय राशि 50 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने की घोषणा की। साथ ही अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार श्रमिकों के लिए मासिक सीजन टिकट एमएसटी जारी किया जाएगा, इससे घर से रेल अथवा बस से कार्यस्थल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। यह कार्ड 50 किमी तक की यात्रा के लिए मान्य होगा। पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए 50 हजार रुपए का अनुदान और हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, पैर के घुटने की सर्जरी, कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त भी 20 हजार रुपए का अनुदान निर्माणी श्रमिकों को मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 250 करोड़ रूपये का नवीन मद में प्रावधान किया है। बेरोजगारी भत्ता योजना के पात्र पाए गए 66 हजार 256 युवाओं के खाते में 16 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार करते हुए इसे नगर पंचायतों में भी लागू किया है। इस योजना में 4 लाख 99 हजार से अधिक लोगों के बैंक खाते में अब तक 476.62 करोड़ की राशि अंतरित की गई है।

सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की भी चिंता करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय वर्ष 2018 तक 2,500 रूपए प्रतिमाह था, जिसे बढ़ाकर 3,250 रूपए किया गया। वर्ष 2022-2023 में इसे बढ़ाकर 5,000 रूपए कर दिया गया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय वर्ष 2018 तक 3,250 रूपए प्रतिमाह था, जिसे बढ़ाकर 4,500 रूपए किया गया। वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 7,500 रूपए किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय वर्ष 2018 तक 5,000 रूपए प्रतिमाह था, जिसे 6,500 रूपए किया गया। वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 हजार रूपए किया गया।

मध्यान्ह भोजन रसोईयों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 1,800 रूपए की गई है। स्कूल स्वच्छताकर्मियों का मानदेय 2,500 रूपए से बढ़ाकर 2,800 रूपए कर दिया गया है। मितानिनों को राज्य मद से 2,200 रूपए प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वृद्ध पेंशन, विधवा, निराश्रित पेंशन की राशि को 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए कर दिया गया है। स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्यों को 500 रूपये मानदेय प्रतिमाह मिलेगा।

ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। सरकार ने ग्राम कोटवारों को दिए जाने वाले मानदेय की दरों में भी वृद्धि की है, जिसके अनुसार 2,250 के स्थान पर 3,000 रूपए, 3,375 के स्थान पर 4,500 रूपए, 4,050 के स्थान पर 5,500 रूपए और 4,500 के स्थान पर 6,000 रूपए किया गया है। होमगार्ड के जवानों का मानदेय न्यूनतम 6300 से अधिकतम 6420 रूपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी की गई है। ग्राम पटेलो का मानदेय 2000 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए प्रतिमाह किया गया है

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के नये आयाम

नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है. राज्य शासन द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच 159 एमएमआर वाले छत्तीसगढ़ का एमएमआर अब घटकर 137 पर पहुंच गया है. कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है. छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से अब तक 2 लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण मुक्त तथा एक लाख 50 हजार महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं. एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए (आयरन फोलिक एसिड) सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है.

महिलाओं को सशक्त बनाना है तो स्वास्थ्य-शिक्षा के साथ-साथ उन्हें अधिकार और आगे बढ़ने के सुरक्षित अवसर देने होंगे. उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नये रास्ते बनाना भी जरूरी है. इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है. महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ा यह दृष्टिकोण उनके लिए विकास के नये आयाम खोलता है.

बिहान से जुड़ी है ढाई लाख महिला समूह - छत्तीसगढ़ में महिलाओं की प्रगति के लिए अपनाई गई नीतियों और उनके संरक्षण का ही परिणाम है, कि यहां वनोपज के कारोबार से 50 हजार से अधिक महिलाएं जुड़कर छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहीं हैं, वहीं जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्रामीण महिलाएं, ग्राम सभा सदस्यों के रूप में खुद के लिए नीतियां भी तैयार कर रही हैं. प्रदेश में करीब 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा चुके हैं, जहां महिलाओं को अच्छा रोजगार और अच्छी आय मिल रही है. महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने लगभग चार हजार बहनें बीसी सखी के रूप में चलते-फिरते बैंक के रूप में बैंकिंग सुविधाएं दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से करीब 27 लाख गरीब परिवारों की महिलाएं 02 लाख 54 हजार स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं.

महिलाओं के श्रम से चमका डेनेक्स - बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों से साहस के साथ मोर्चा ले रहीं बस्तर की दंतेश्वरी फाइटर्स अपने पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. गोधन न्याय योजना के तहत गांव-गांव में बनाए गए गौठानों में लगभग 45 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है. ये महिलाएं गौठानों में आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से न सिर्फ सशक्त

बन रही हैं, बल्कि अपने परिवारों के लिए भी संबल बन गई हैं. गोठानों बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी-मार्ट स्टोर जैसी नई अवधारणा से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा हैं. महिलाओं द्वारा तैयार सामाग्री को बाजार मिल रहा हैं. बस्तर के आदिवासी जिले दंतेवाड़ा की डेनेक्स गारमेंट फैक्टरी में काम कर रही महिलाओं ने देश-विदेश में डेनेक्स ब्रांड को लोकप्रिय बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है. बीजापुर की महिलाओं का महुआ लड्डु, कोंडागांव का तिखुर शेक, सुकमा की ईमली-कैंडी और नारायणपुर का फूल झाडू भी प्रसिद्ध हो चुका है.

महिला कोष का बजट 25 करोड़- महिला कोष से ऋण लेकर आर्थिक गतिविधि जुड़ी महिला समूहों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समूह द्वारा लिए गए पुराने 12 करोड़ रूपये के ऋण माफ कर दिये हैं. साथ ही ऋण लेने की सीमा को भी दो से चार गुना तक बढ़ा दिया है. महिला कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋण सीमा में भी दोगुनी वृद्धि की गई है. महिला कोष के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है. पूर्व वर्षों में महिला कोष को एक या दो करोड़ वार्षिक आबंटन उपलब्ध होता था मगर वर्ष 2023-24 में 25 करोड़ रूपए का वार्षिक बजट उपलब्ध कराया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा 10 हजार 500 से अधिक महिलाओं के लिए पिछले 5 सालों में सर्वाधिक 10 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक ऋण राशि स्वीकृत की गई है. नई कौशल्या समृद्धि योजना शुरू करने की योजना है, इसमें महिलाओं को व्यवसाय के लिए आसान शर्तों पर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा. इसके लिए 25 करोड़ रूपए का बजट अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया है.

महिला उद्यमिता नीति – महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, राज्य का विकास उतनी ही तेजी से होगा, इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में महिलाओं की क्षमता को एक नई ऊंचाई देने के लिए महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू कर दी गई है. इसमें महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ कई प्रकार की छूट का प्रवाधान किया गया है. राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 10 से 50 लाख रूपए ऋण के साथ विद्युत शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट, परिवहन अनुदान, मण्डी शुल्क से छूट, किराया अनुदान जैसे कई प्रावधान किये गए हैं. महिला स्व-सहायता समूहों और महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है, इससे उद्योग एवं व्यापार में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी.

राशन कार्ड और मकान महिलाओं के नाम पर – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भूमि और संपत्ति पंजीयन पर एक प्रतिशत की छूट दी जा रही है. राशन कार्ड और आवास आबंटन महिलाओं के नाम पर किए जा रहे है. सरकारी सेवाओं में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेजों की छानबीन के कार्यों के लिए बनाई गई समितियों में एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रखने की व्यवस्था बनाई गई है. लैंगिक अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक समिति बनाई गई है, जो इस मामले की जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही करने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं.

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल - हर संभाग में कामकाजी हॉस्टल के साथ जिला मुख्यालयों में महिला हॉस्टल बनाए जाने की शुरूआत की गई है. थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क संचालित हैं, जिससे महिलाएं मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा सकें. छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सहायता के लिए अभिव्यक्ति एप बनाया गया है. महिला हेल्पलाईन नम्बर 181 और सखी सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता और आश्रय भी प्रदान किया जा रहा है. अब तक 37 हजार 158 पीड़ित महिलाओं को सहायता और 13 हजार 750 महिलाओं को आश्रय दिया गया है. नवा बिहान योजना के माध्यम से घरेलू हिंसा के प्रकरणों में 4331 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है.

बढ़ा मान और बढ़ा मानदेय - राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य की देखभाल कर रहीं महिला कर्मियों के मानदेय में वृद्धि कर उनका सम्मान भी बढ़ाया है. इस साल बजट में प्रदेश के 46 हजार 660 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करते हुए अब इसे 06 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है. आंगनवाड़ी साहियकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रुपए से बढ़ाकर 05 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है. मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 07 हजार 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. मितानिन बहनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रति माह की दर से मानदेय देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है, इससे प्रदेश की 72 हजार मितानिनों की पुरानी मांग पूरी हुई है. इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है, जिससे बहुत सी ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी.

कन्या विवाह के लिए अब 50 हजार - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामाजिक पृष्टिभूमि में महिलाओं और उनके परिवारों के मान-सम्मान का भी ध्यान रखते हुए कई निर्णय लिए हैं. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को भी अपने कार्यकाल में दो बार बढ़ाकर बेटियों के विवाह के लिए बड़ी राहत दी है. 2019 में यह राशि 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई और अब बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है. निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है.

9 नए महिला महाविद्यालय - महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाकर जागरूकता लाना भी आवश्यक है. इसे देखते हुए पिछले साल 2239 विधिक व महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया गया. इस वर्ष महिला जागृति शिविर मद के बजट में दोगुनी वृद्धि कर 4.85 करोड़ से बढ़ाकर 9.33 करोड़ किया गया. इसके साथ ही राज्य महिला आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारियों और कानूनों की जानकारी भी दी जा रही हैं. राज्य की 9 जिला मुख्यालयों में नए महिला महाविद्यालय की शुरूआत के साथ महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोले गए हैं.

स्थानीय औषधियों पर आधारित उद्योग की स्थापना से होगा लाभः सीएसआईडीसी अध्यक्ष नंदकुमार साय

रायपुर. नंदकुमार साय ने छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद उद्योग भवन में सीएसआईडीसी के अधिकारियों की बैठक ली और राज्य में औद्योगिक प्रगति के संबंध पर चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के उत्थान के लिए सतत कार्य करना है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की अधिक से अधिक स्थापना हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके. अध्यक्ष श्री साय ने स्थानीय कृषि, खाद्य, लघु वनोपज, औषधीय वनोपज एवं हर्बल उपज पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों के जड़ी-बूटी संबंधी प्राचीन ज्ञान के आधार पर स्थानीय औषधियों एवं हर्बल उपज पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना से उनका मूल्य संवर्धन संभव हो सकेगा एवं इसका लाभ सभी को मिलेगा. अध्यक्ष श्री साय ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो रहे फूड पार्कों की स्थापना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. बैठक में संचालक उद्योग सह प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी डॉ. सारांश मित्तर ने अध्यक्ष श्री साय को राज्य में फूड पार्कों, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क एवं प्लास्टिक पार्क के निर्माण के लिए किए जा रहे अधोसंरचना विकास के बारे में बताया. उन्होंने जानकारी दी की ग्रामीणों की आय में वृद्धि एवं समावेशी विकास के लिए छोटे औद्योगिक क्षेत्रों एवं फूड पार्कों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है. डॉ. मित्तर ने निवेशकों एवं उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाईन किए गए विभिन्न अनुदान व छूट हेतु आवेदन, भूमि आबंटन, वाटर कनेक्शन, देयक भुगतान आदि के संबंध में भी जानकारी दी. डॉ. मित्तर ने बताया की उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की आबंटन दरों में कमी की गई है. लीज रेंट 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है. उद्योगों को आबंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने की सुविधा दी गई है. उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्टार्ट-अप उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए घोषित विशेष पैकेज के संबंध में जानकारी दी. बैठक में सीएसआईडीसी के कार्यपालक संचालक अनिल कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक संजय सिन्हा व अजय श्रीवास्तव, महाप्रबंधक ओ. पी. बंजारे एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे.

वर्मी कंपोस्ट बैग बना आय का जरिया

गौठानों में महिलाओं को मिला रोजगार
पर्यावरण बचाने बैग कर रहीं तैयार
ऑर्डर मिल रहे लगातार, तेजी से बढ़ा व्यापार

ये चेहरे पर मुस्कान बिखर रही हैं, ये कहीं और से नहीं, बल्कि गौठानों से आई हैं. महिलाओं में जो खुशियां बरस रही हैं, ये सरकारी योजनाओं और मेहनत का फल है. ये महिलाएं गौठानों और सी-मार्ट में वर्मी कंपोस्ट बैग क्रय कर रही हैं. इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं. वर्मी कंपोस्ट बैग आय का जरिया बन गया हैरु गौठानों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है. महिलाएं भी पर्यावरण बचाने बैग तैयार कर रहीं हैं. महिलाओं को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, तेजी से व्यापार बढ़ रहा है. राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगित पार्क (रीपा) के अंतर्गत महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखर रही है.

पर्यावरण के लिए खतरा बना प्लास्टिक

दरअसल, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण न हो तथा इंसानों और मवेशियों को भी इससे नुकसान न हो इसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस प्रतिबंध के चलते गौठानों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का नया साधन उपलब्ध हुआ है. गौठानों में महिला स्व सहायता समूह अब वर्मी कंपोस्ट से बैग तैयार कर रही हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पर्यावरण को संरक्षण दे रहा है. इससे आय भी अर्जित हो रही है.

रोजगार से जुड़ी समूह की महिलाएं

राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगित पार्क (रीपा) के अंतर्गत मानक रूप वर्मी कम्पोस्ट बैग बनाने का उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं. इसके लिए मशीन की स्थापना की जा रही है, जिससे समूह की महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है. इस रोजगार से जुड़ी समूह की महिलाएं अब अमानक प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए वैकल्पिक उत्पाद जैसे वर्मी कम्पोस्ट बैग, थैले, कागज के लिफाफे और दूसरे सामान बनाने की ओर अग्रसर हैं.

बिरकोनी गौठान की ग्रामीण महिलाएं कर रहीं कमाई

इसी तर्ज पर महिला समूह अमानक प्लास्टिक पर असरदार तरीके से बैन लगाने के लिए सस्ते दरों पर वैकल्पिक सामग्रियां उपलब्ध करा रही हैं. इसी क्रम में महासमुंद जिले के बिरकोनी गौठान की ग्रामीण महिलाएं सिरपुर वर्मी कम्पोस्ट नाम से बैग निर्मित कर रही हैं.

समूहों को रोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना

राज्य सरकार द्वारा नो प्लास्टिक मुहिम के तहत रीपा के माध्यम से महिला समूहों को रोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना बनायी गयी है. बिरकोनी की राम जानकी स्व सहायता महिला समूह द्वारा बनाए गए वर्मी कम्पोस्ट बैग एवं अन्य पैकिंग सामग्री, जरूरत अनुसार गौठनों में और सी-मार्ट में उपलब्ध हो रहे हैं.

5 हजार वर्मी कम्पोस्ट बैग क्रय

राम जानकी स्व-सहायता समूह बिरकोनी की रेखा नागपुरे ने बताया कि अब तक उन्होंने 5 हजार वर्मी कम्पोस्ट बैग जिले की गौठानों में मांग अनुसार उपलब्ध कराया है तथा उन्हें और भी ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं. समूह की अध्यक्ष के अनुसार यह बैग मानक के अनुरूप और काफी हल्के और मजबूत होने के कारण लाने ले जाने में आसान है जिसकी वजह से इनकी मांग ज्यादा है.

जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडलके रुप में उभरी नरवा योजना सिंचाई सुविधाओं का हुआ विस्तार, बारिश पर किसानों की निर्भरता हुई कम

छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा योजना अन्नदाताओं के लिए संजीवनी का काम कर रही है. अब किसानों को पानी के लिए बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है. नरवा के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है. साथ ही वे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं. नरवा स्ट्रक्चर ब्रशवुड, बिना लागत भूमिगत जल के रिचार्ज करने का एक बेहतरीन उदाहरण है. राज्य में स्थित वन क्षेत्रों में नालों में संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है. जिससे क्षेत्रों में उपस्थित जीवों को अपना चारा-पानी खोजने के लिए रहवासी क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ग्रामीण और किसानों को प्रशासन द्वारा पेयजल और सिंचाई के साधन विकसित कराए जा रहे हैं. जिससे जल की उपलब्धता सुनिश्चित होने से किसानों को खेती-बाड़ी करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.

जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य छत्तीसगढ़ जहां धान, विभिन्न फसले, फल, साग-सब्जी का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही कृषि विकास और कृषक कल्याण दोनों एक दूसरे के दो पहलू हैं, और प्रदेश सरकार को सुराजी गांव योजना इन सभी विकास के पहलुओं को निखार रही है. छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजनांतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देते हुए लोगों को गांव में ही पूर्ण रोजगार देने व गांव के विकास के लिए नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी को विकसित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. जिससे अब गांवों की तस्वीर बदल रही है. भूगर्भीय जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में नरवा कार्यक्रम के माध्यम से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके.

वर्षा के जल पर निर्भर किसानों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है. दुर्ग जिले में नदी-नालों के संरक्षण और संवर्धन में निरंतर से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों को खेती किसानी और पशुपालन जैसी गतिविधियों के लिए बड़ी सुविधा मिल रही है.

छत्तीसगढ़ में नालों को नरवा कहा जाता है. इस योजना के तहत राज्य के नालों पर चेकडेम बना कर पानी रोकना और उस पानी को खेतों की सिंचाई के लिये उपलब्ध कराना है. इसके अलावा नालों के जरिए बारिश का जो पानी बह जाता है, उसे रोक कर भूगर्भीय जल को रिचार्ज करना है. नरवा योजना मुख्यतः इस वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित है कि पानी का वेग कम होने से धरती का रिचार्ज तेजी से होता है. क्योंकि धरती को जल सोखने के लिए अधिक समय मिलता है.

अक्सर बरसाती नालों में जितने तेजी से पानी चढ़ता है उतने ही तेजी से उतर भी जाता है. अब किसानों को खरीफ के साथ ही रबी फसलों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर भी बढ़ रहा है. साथ ही मनरेगा के तहत नरवा विकासकार्यों में शामिल होकर ग्रामीणों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है.

दुर्ग जिले में नरवा अंतर्गत एरिया ट्रीटमेंट और ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट के कार्यों को नया आकार दिया गया है. एरिया ट्रीटमेंट के लिए कच्ची नाली, निजी डबरी, नया तालाब, वृक्षारोपण, वाटर अब्सोरप्शन ट्रेंच, भूमि सुधार, रिचार्ज पिट और कुओं का निर्माण किया गया है. ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट के लिए नाला पुनरोद्धार एवं गहरीकरण, अन्य नवीन नरवा जीर्णोद्वार, चेक डेम, चेक डेम जीर्णोद्वार, ब्रशवूड चेक डेम, रिचार्ज पिट इत्यादि का निर्माण किया गया है. नरवा अंतर्गत स्वीकृत कार्य के आंकड़े प्रशंसनीय हैं. डीपीआर में कुल 6207 कार्य लिए गए जिनमें से 6164 कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है. 5890 कार्य पूरे हो चुके हैं. 304 ग्राम पंचायतों में कुल 196 नरवा बनाये गए हैं और नरवा का उपचार किया गया है. 89 डाईक के साथ कुल 167660.81 हे. का जल संग्रहण क्षेत्र बनाया गया है.

मिट्टी में नमी की मात्रा में वृद्धि का आंकलन क्षेत्र में वनस्पति अच्छादन और कृषि की उत्पादकता की स्थिति के आधार पर किया जाता है. नमी के चलते ही पौधों की जड़े फैलती है और पौधे नमी के साथ हो मिट्टी से अपना भोजन लेते हैं. ज्यादा पानी की वजह से फसल में आद्र गलन व जड़ गलन इस तरह के फफूंदजनित रोग की समस्या आती है. भूमिगत जल सतह की स्थिति का आंकलन वर्ष में दो बार किया जाता है. प्री-मॉनसून मार्च से मई तक और पोस्ट-मॉनसून अक्टूबर से दिसंबर तक होता है.

नरवा में प्रवाह का आंकलन रुपये लीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से नरवा में पानी के प्रवाह का आंकलन किया जाता है. जब नरवा में पानी की मात्रा अच्छी होती है तो किसान को खेती में सुविधा मिलती है. इस सूचक के प्रभाव का आकलन रबी और खरीफ फसल के सिंचित रकबे में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है. किसानों द्वारा नाले के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ी है.

समृद्ध फसलों के लिए मददगार साबित हुई योजना

गजरा नाला वॉटर शेड में कम बारिश से जलभराव होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिल रही है. जिससे फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है. आस-पास के लिए हैंड पंप और बोर में भू-जल स्तर बढ़ रहा है. ग्राम पंचायत अकतई, औरी, पौहा और रानीतराई में नाले में बोरी बंधान से अल्पवर्षा का पानी संकलित हुआ है. इस जलभराव से किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी की व्यवस्था हुई है. समृद्ध फसलों के लिए यह मददगार साबित हो रहा है. पंद्रह कि.मी. के लुमती नाले में ट्रीटमेंट होने पर डेढ़ हजार किसानों कर रहे रबी फसल का उत्पादन 745 हेक्टेयर में बोर के माध्यम से 1610 किसान कर रहे हैं. जिससे भूमिगत जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई हैं.

जल संरक्षण का राष्ट्रीय मॉडल

नाले के दोनों किनारों में 500 मीटर तक किसान पहले बोर चलाते थे, अब नाले से पानी ले रहे हैं. कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा धमधा में विकास कार्यों का निरंतर निरीक्षण करते हैं. मानसून की अमृत बूंदों के स्वागत के लिए तैयार नरवा स्ट्रक्चर के माध्यम से जलस्तर पांच इंच तक बढ़ने की उम्मीद है. नरवा के दो चरणों के काम सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं, 586 इंच जलस्तर बढ़ गया है जिससे पंद्रह हजार श्रमिकों की मेहनत रंग लाई है. इस योजना के माध्यम से न सिर्फ भूजल स्तर के गिरावट में कमी आ रही है. बल्कि नरवा की साफ-सफाई और भूमि सुधारकर नालों के क्षेत्रफल को भी बढ़ाया जा रहा है. इस योजना का लक्ष्य यह भी है कि गर्मियों के मौसम में कुआं, हैंडपंप और बोरवेल आदि में भी पानी के स्तर में कमी ना आए और राज्य के किसान आसानी से खेती-बाड़ी कर सकें. साल भर जल की उपलब्धता बनी रहे और किसान आत्मनिर्भर और सशक्त रहे. जल संरक्षण में नरवा एक राष्ट्रीय मॉडल की तरह उभर रहा है.

तीरंदाजी के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार

एकलव्य जैसी प्रतिभाओं को अकादमियों के जरिए मिल रहे द्रोण जैसे गुरु

एकलव्य की कथा सभी जानते हैं. किस तरह गुरु नहीं होने से एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, उसे सामने रखकर तीरंदाजी का अभ्यास करता है. कुछ इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कुछ साल पहले तक एकलव्य जैसी प्रतिभाओं को निखारने के लिए अकादमी नहीं थी. ना इंस्टीटच्यूट थे और ना ही द्रोण जैसे गुरु थे.लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खेलों की आधारभूत संरचना तैयार करने की पहल शुरू की है. जिससे एकलव्य जैसे हजारों प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खेल की राह आसान हुई है. भारत के संदर्भ में देखें तो तीरंदाजी स्पर्धाओं में आदिवासी इलाकों से ही अधिक संख्या में प्रतिभाओं ने अंतरराष्ट्रीय मंच में भारत का नाम बढ़ाया है. अब जरुरत थी तो ऐसे हुनर को और आगे बढ़ाने की.

भूपेश सरकार ने तीरंदाजी के लिए खास तौर पर अधोसंरचना तैयार की है. राज्य स्तर पर हुई स्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इनकी प्रतिभा को नये सिरे से गढ़ने की व्यवस्था की गई. बिलासपुर के बहतराई में तीरंदाजी अकादमी की शुरुआत हुई. आवासीय अकादमी होने की वजह से दिन का ज्यादातर समय प्रैक्टिस में बीतता है और ये सेंटर 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बन गया. खेलो इंडिया प्रतियोगिता में यहां के खिलाड़ियों ने कमाल किया। कुबेर जगत को स्वर्ण पदक मिला और गीता यादव ने रजत पदक जीता.

तीरंदाजी से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि तीरंदाजी के लिए एकाग्रता के साथ ही दृश्य संतुलन और शारीरिक संतुलन महत्वपूर्ण है. किस तरह से शारीरिक संतुलन रखकर बेहतर लक्ष्य पाया जा सकता है, इसके लिए कोचिंग का बड़ा सहयोग होता है. इसके साथ ही न्यूट्रीशन का भी बहुत महत्व होता है. रायपुर तीरंदाजी अकादमी में इसके लिए विशेष रूप से न्यूट्रिस्ट का पद सृजित किया गया है. इसके साथ ही शिवतराई उपकेंद्र में 54 खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा है. रायपुर में गैर आवासीय तीरंदाजी अकादमी बनाई गई है. यहां 60 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है.

तीरंदाजी में प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य शासन लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी शुरू करने की घोषणा की. 40 सीटर ये अकादमी पूरी तरह आवासीय होगी. इसके माध्यम से 40 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिल सकेगा. जशपुर में तीरंदाजी अकादमी 30 सीटर प्रस्तावित है. ये भी पूरी तरह आवासीय होगी

इस कंपनी के शेयर का बाजार में जलवा

1 लाख के बन गए 51 लाख

रायपुर. 13 अप्रैल 2022 को ₹8 के स्तर से कारोबार शुरू करने के बाद हार्डविन इंडिया लिमिटेड के शेयरों ने ₹40 का स्तर छू लिया है. हार्डविन इंडिया लिमिटेड के शेयरों ने महज 3 साल की अवधि में निवेशकों को 5000% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. शुक्रवार को शेयर बाजार के टॉप गेनर्स में शामिल हार्डविन इंडिया के शेयर 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गए और ₹40 के स्तर को छू गए.

हार्डविन इंडिया के शेयर की कीमत में अचानक वृद्धि का कारण यह है कि हार्डविन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने हार्डविन इंडिया लॉक्स लिमिटेड के विलय को मंजूरी देने का फैसला किया है. शुक्रवार को शेयर बाजार में हार्डविन इंडिया के शेयरों में बंपर खरीदारी देखने को मिली.

पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में हार्डविन इंडिया का रेवेन्यू करीब 30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. साल-दर-साल आधार पर इसमें 10% की कमी आई है.

मार्च तिमाही में हार्डविन इंडिया का परिचालन मुनाफा 118 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 5.66 करोड़ रुपये रहा. हार्डविन इंडिया लिमिटेड ने पिछले एक-दो साल में अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है.

20 जून 2022 को हार्डविन इंडिया के शेयर ₹11 के स्तर पर थे, जो 1 साल से भी कम समय में ₹51 के स्तर को छू चुके हैं. इस तरह सिर्फ 1 साल की अवधि में हार्डविन इंडिया लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को 300% रिटर्न दिया है. 2 साल की अवधि में हार्डविन के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है.

हार्डविन इंडिया एक हार्डवेयर फिटिंग निर्माण कंपनी है और बिल्डर को संपूर्ण समाधान प्रदान करती है. हार्डविन इंडिया किचन प्रोडक्ट्स, मल्टी प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स के कारोबार में भी शामिल है. हार्डविन इंडिया के शेयरों में 1 लाख रुपये निवेश करने वालों को इस समय 97 लाख रुपये का बंपर रिटर्न मिल रहा है.

11611

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

DR. C.V.RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur

AN AISECT GROUP UNIVERSITY

Approved by : PCI | AICTE | NCTE | BCI | Member of : AIU | Recognized by : UGC | A NAAC Accredited University

ADMISSION OPEN [2023-24]

PROGRAMMES OFFERED

B.VOC / D.VOC

- Automobile Servicing
- IT Application Development
- Banking Financial Services and Insurance
- Construction
- Production Technology
- AC & Refrigeration
- House Keeping
- Home Care
- Hospital Administration

LAW

- LL.M. | LL.B.
- B.A. (LL.B.)
- B.Com.(LL.B.)

SCIENCE

- **B.Sc.** (Mathematics, Biology, Microbiology, Biotech, Computer Science)
- **M.Sc.** (Physics, Chemistry, Mathematics, Micro-biology, Botany, Biotech, Zoology, Electronics, Rural Technology)
- PGDRD

EDUCATION

- B.Ed. | M.Ed.

PHYSICAL EDUCATION

- B.P.E.S. | M.P.E.S.

MANAGEMENT

- B.B.A.| M.B.A. |PGDBM

COMMERCE

- B.Com. | M.Com.

INFORMATION TECH.

- M.Sc. (IT) • M.Sc. (CS)
- P. G.D.C.A.
- B.C.A. • D.C.A.

ARTS

- B.A.
- M.A.
  - **Linguistics-** (English, Hindi, Chhattisgarhi, Sanskrit)
  - **Social Science -** (History, Geography, Economics, Political Science, Education)
- B.Lib. | M.Lib.
- M.S.W. (Social Work)
- B.J. | M.J.
- PERFORMING & FINE ARTS (Indian Music (Vocal) Kathak, Tabla, Guitar)
  B.F.A. | M.F.A.

Research Programmes

- Ph.D

ENGINEERING & TECHNOLOGY

B.TECH.

Mechanical Engineering | Civil Engineering
Electrical Engineering | Electronics & Comm. Engg
Computer Science Engg | Electrical & Electronics Engg.

POLYTECHNIC DIPLOMA

Civil Engineering | Mechanical Engineering
Computer Science Engg. | Electrical Engineering

M. TECH.

Digital Communication | Power System
Computer Science Engg. | Production Engineering
Software Engineering | VLSI

PHARMACEUTICAL SCIENCES

B. PHARM

D. PHARM

M. PHARM

Other Initiatives Taken Up By CVRU

Solar Power
We have a 10 KW solar power generation system and a 5 KW capacity solar cell

Herbal Medicinal Garden
Our campus garden has around 425 plants with medicinal value and a variety of herbs and shrubs, as part of our Go Green Campus campaign

Biogas
We use biogas in laboratories from our plant which produces with more than 1000 cm³ of capacity

NSDC and NPTEL Partnership
To ensure an advantage in placements, we train in skills with the NSDC and virtual courses designed by IIT faculties with the NPTEL

Incubation Centre
Incubation Centre at CVRU campus 5 crore project fromdepartment of science & technology (DST), govt of India (ITBI) inclusive technology business Incubator NIDHI-DSTscheme

Village Adoption
We have adopted five villages near the university through the NSS and NCC & Uannat Bharat Abhiyan

TOP RECRUITERS OF AGU

Paytm | NIIT | Star | Collabera | genpact | LANCO | amazon | AMERICAN EXPRESS | Tech Mahindra | iON | vedanta | vivo | wipro | Infosys | SHRIRAM | IndusInd Bank | SAMSUNG | Vedisoft | EXIDE | Axis Bank | Capgemini | CODING NINJAS | YAHOO! | Prakash | HCLTech | Fullerton India | HCL

AdPrayas

ADMISSION HELPLINE: 6261-900581/82

www.cvru.ac.in

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.), Phone: +91-7753-25801, Email: info@cvru.ac.in, admissions@cvru.ac.in

प्रदेश म मया अऊ एकता के बगरही रंग
लइका सियान सबो झन खेलहीं संग-संग

पारंपरिक एवं देसी खेलों का महाकुंभ

Chhattisgarhia OLYMPICS 2023

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक

17 जुलाई - 27 सितंबर 2023

गिल्ली-डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी
खो-खो, रस्साकशी, बाटी(कंचा), बिल्लस, फुगड़ी
गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मी. दौड़, लम्बी कूद
रस्सीकूद, कुश्ती

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

खेल विधाएं
16

प्रतिभागी
30 लाख से ज्यादा

आयु वर्ग (महिला एवं पुरुष)
18 वर्ष तक | 18-40 वर्ष तक | 40 वर्ष से अधिक

खेल आयोजन स्तर
राजीव युवा मितान क्लब, जोन,
विकासखंड/नगरीय क्लस्टर, जिला, संभाग एवं राज्य

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

R.O. No. - 12575/ 203